



देवरिया अवैध मज़ार मामला:

फर्जीवाड़ा बिना मिलीभगत असंभव

देवरिया। बंजर भूमि पर मजार व कब्रिस्तान का फर्जी इंद्राज कराने के मामले में तहसील प्रशासन अब पूरे प्रकरण की कुंडली तैयार कर रहा है। जांच की जद में तत्कालीन लेखपालों व अन्य राजस्वकर्मियों की भूमिका भी आ सकती है।

प्रशासन का मानना है कि कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना यह फर्जीवाड़ा संभव नहीं था। फिलहाल मजार की देखरेख करने वाली समिति के उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है, जो फर्जी इंद्राज के समय जिम्मेदार पदों पर थे।

गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज से सटे मेहड़ा नगर अंदर, तप्पा धतुरा में स्थित मजार व कब्रिस्तान नान-जेड ए श्रेणी की भूमि पर बना था। वर्ष 1399- फसली की खतौनी में बंजर दर्ज था, जिसका कुल रकबा 0.124 हेक्टेयर है। वर्ष 1992 में एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय से जारी एक फर्जी परवाना प्रस्तुत कर भूमि को मजार व कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करा दिया गया था।

इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से राजस्व अभिलेख दुरुस्ती का वाद



दाखिल किया गया था। एसडीएम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभिलेख दुरुस्त करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में तहसील प्रशासन ने भूमि को पुनः बंजर दर्ज किया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में स्पष्ट किया था कि तत्कालीन लेखपालों व कलेक्टर कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना इस प्रकार का फर्जीवाड़ा संभव नहीं है।

प्रशासन अब उस समय तैनात लेखपालों, कलेक्टर कर्मचारियों और समिति से जुड़े लोगों की भूमिका की गहनता से जांच कर रहा है। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने बताया कि तहसीलदार को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर करोड़ों

रुपये मूल्य की सरकारी भूमि हड़पने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले अप्रैल खख में केंद्रीय विद्यालय को आवंटित भूमि से जुड़े अभिलेखों में भी कूटरचना का मामला सामने आ चुका है।

उस प्रकरण में राजस्व अभिलेखापाल संजय कुमार की ओर से काबिज लोगों के साथ ही अभिलेखागार के कस्टोडियन, नायब हिंदी और बस्ता बरदार (चपरासी) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना अभी जारी है।

शहर से सटे अमेठी (नगर बाहर) क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए 4-क हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। कुछ लोगों ने इस भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए कथित रूप से कूटरचित अभिलेखों के आधार पर न्यायालयों में वाद दाखिल किए।

डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर तत्कालीन सीआरओ जलराजन चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच 1332 फसली खतौनी से लेकर चकबंदी जिल्द तक में कूटरचना की गई थी।

हड़ताल और सरकार के दबाव के बाद ब्लिंकिट ने समय सीमा हटाई ज़ेप्टो-स्विगी-ज़ोमैटो भी करेंगे संशोधन

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई मंचों पर 10-15 मिनट की डिलीवरी सर्विस की आलोचना हो रही थी। विशेषज्ञों का मानना था कि इतने कम समय में डिलीवरी का दबाव राइडर्स को तेज गाड़ी चलाने और रेड लाइट जंप करने के लिए मजबूर करता है। सड़क सुरक्षा से जुड़े संगठनों ने भी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

अब 10 मिनट वाली पाबंदी हटने से आपका सामान घर पहुंचने में 5-10 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। अब कंपनियां तेजी से सामान पहुंचाने के साथ सड़क पर चलने वाले राइडर्स की सुरक्षा को भी ध्यान में रखेंगी। यानी, इसे भी प्राथमिकता बनाएंगी।

यह केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं है। कंपनियों को अपने एप के एल्गोरिदम और वर्किंग मॉडल बदलने होंगे ताकि राइडर्स पर दबाव कम हो सके।



गिग वर्कर्स के लिए 'सोशल सि-क्योरिटी कोड 2020' के तहत नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, जिसमें बीमा और पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर नए कानून के तहत भारी जुर्माना लगेगा और नेशनल सोशल सिक््योरिटी बोर्ड उन पर सख्त निगरानी रखेगा। हालांकि, ये जुर्माना कितना

होगा ये अभी साफ नहीं है।

क्विक कॉमर्स कंपनियों का पूरा मॉडल 'ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर' पर टिका है। जब 10 मिनट की पाबंदी थी, तो राइडर एक घंटे में 1 से 2 ऑर्डर पूरे करने की कोशिश करता था। अब समय बढ़ने से शायद वह एक घंटे में 1 या 2 ऑर्डर ही कर पाए। चूंकि राइडर्स को हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं, इसलिए ऑर्डर कम

होने से उनकी रोज की कुल कमाई पर असर पड़ सकता है।

सरकार और ब्लिंकिट-जेप्टो जैसी कंपनियों के बीच सहमति बनी कि 10 मिनट का वादा ब्रांडिंग से हटाया जाएगा। वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

पुख्ता आंकड़ों के बजाय संसद में इनकी 'पीड़ा और बदहाली' पर चर्चा हुई, जिसमें दबाव और खराब मौसम में जान जोखिम में डालने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

अब कंपनियां 'फास्ट डिलीवरी' के बजाय 'ज्यादा वैरायटी' पर फोकस कर रही हैं, जैसे ब्लिंकिट अब 10 मिनट के बजाय 30,000+ प्रोडक्ट्स की रेंज का प्रचार कर रहा है।

विरोध का ठोस नतीजा यह निकला कि सरकार ने हस्तक्षेप किया और अब गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कामकाजी

माहौल का अधिकार मिला है।

अब तक फोकस सिर्फ सामान पहुंचाने पर था। अब कंपनियां अपनी सर्विस में 'वैल्यू एडिशन' करेंगी। मसलन, फल और सब्जियां कितनी फ्रेश हैं, पैकिंग कितनी सुरक्षित है और कस्टमर सपोर्ट कितना अच्छा है। अब मुकाबला इस बात पर होगा कि कौन सा ब्रांड सबसे भरोसेमंद है, न कि सबसे तेज।

कम कमाई और 10 मिनट में डिलीवरी के प्रेशर से परेशान गिग वर्कर्स ने न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को हड़ताल की थी, जिसमें स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनियों के राइडर्स शामिल थे। इससे पहले गिग वर्कर्स ने 25 दिसंबर को क्रिसमस पर भी हड़ताल की थी। इन हड़तालों में गिग वर्कर्स ने 10 मिनट में डिलीवरी मॉडल को खत्म करने समेत कई मांगों की थीं।

भारत का बुलडोज़र राज देश को किधर लेजा रहा?



Ali Aadil Khan
Editor

दो साल में 1,50,000 से ज्यादा घर ध्वस्त किए गए और 7,38,000 लोग बेघर हुए, दुखद यह रहा इसको बुलडोज़र न्याय का नाम दे दिया गया। जबकि दूसरी राजनितिक पार्टियां इसको सरकार की दमनकारी नीति बता रही है, जो अंग्रेजी दौर में भी नहीं हुआ था। अपने ही मुल्क में लोग बेगाने हो गए अनजाने बनाये आ रहे हैं, चर्चा में कहा जा रहा है की वर्तमान सरकार अपने ही देशवासियों को जबरदस्ती गद्दार बना रही है। जो सरकार इनके घरों को दुकानों और पूजा स्थलों को

गिरा रही है क्या उससे इन्साफ़ की उम्मीद की जा सकती थी?

बुलडोज़र न्याय की वजह सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण बताया जाता है। अगर यही वजह है तो सरकार कार्रवाई सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्यों नहीं अपना रही? मजे की बात यह है कि ये सब अतिक्रमण सरकारों की मौजूदगी में हो रहा होता है। फर्क इतना है कि सरकारों में बैठी पार्टियों के झंडों के रंग अलग थे और विचारधारा भी।

फर्क यह भी था कि पिछली सरकारें कम से कम बहु संख्यकों यानी हिन्दुओं के साथ तो अन्याय नहीं करती थीं। आजकी सरकारें हिन्दू हितेषी के ढोंग करती हैं और उन्हीं को नुकसान भी पहुंचाती हैं।

बनारस (वाराणसी) में 'दालमंडी' इलाके में हिन्दू व्यापारियों सहित अनेकों कारोबारियों को उजाड़ा गया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रशासन ने इन दुकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर गिराया।

जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है, और भाजपा सरकार ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह कदम उठाया। उधर

व्यापारियों का कहना है कि वे दशकों से वैध तरीके से काम कर रहे थे, जिससे शहर के पारंपरिक ढाँचे और तालमेल पर बुरा असर पड़ा है।

कुल मिलाकर इसका ख़मयाज़ा मुसलमानों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के साथ आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ा है। मगर



यहूदी कम्पनियों को जितना लाभ पिछले 10 वर्षों में भारतीय बाज़ार से हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ।

साथ ही बनारस का बड़ा कारोबार गुजरातियों के हवाले कर दिया गया और बनारस के लोग देखते ही रह गए, हो सकता है किसी सरकार के

ज़हन में यही सामंजस्य और रिवायती तालमेल हो कि गुजरात उत्तर प्रदेश के भी कारोबार पर क़ाबिज़ हो। लेकिन क्या बनारस को भी गुजरात के कारोबार और ज़मीनों में हिस्सा दिया जाएगा?

हालिया दिनों में भारत में यहाँ के मूल निवासियों, आदिवासियों, ईसाइयों और मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया गया उसने मनुवादी लक्ष्य को साफ़ उजागर कर दिया।

लगतें ही उसका घर गिरा दिया जाए।

बुलडोज़र जस्टिस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें दोष सिद्ध होने से पहले सज़ा दी जाती है, क़ानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है, और यह संदेश जाता है कि राज्य स्वयं जज़, जूरी और जल्लाद बन रहा है।

और लगभग यही सब कुछ अंगरेज़ साम्राज्यवाद के दौर में हुआ करता था। जिसके खिलाफ देश की जनता ने असहयोग आंदोलन चलाया और फिर मार भगाया। बुलडोज़र से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन डर से व्यवस्था नहीं चलती। लोकतंत्र की बुनियाद डर नहीं, क़ानून और संविधान हैं। डर और ख़ौफ़ पैदा करना यह तानाशाही की अलामत है। जबकि आज इस तानाशाही को झूठे राष्ट्रभक्ति के चोले में छुपाया गया है, जो देश के साथ बड़ा धोखा और गद्दारी है।

राजधर्म का काम सार्वजनिक रूप से धार्मिक या राजनितिक पाखंड नहीं, डमरू, ढोल बजाना और डुबकी लगाना नहीं, बल्कि जनता के साथ ईसाफ़, समानता, सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ही राजधर्म होता है। सरकार अपना राजधर्म नहीं निभाकर जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करती है, या कहें बागी बनाती है।

सूफ़ी संतों का एक स्वर, 'कौम में अमन' के लिए देशव्यापी अभियान का ऐलान

नई दिल्ली। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से आज नई दिल्ली में 'कौम में अमन के फ़रोग' विषय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश में शांति, आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकजुटता को और मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। इसके बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में काउंसिल ने लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।

संवाददाता सम्मेलन में काउंसिल ने 'मेरा देश, मेरी पहचान' नारे के तहत एक राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य और प्रमुख शहरों में जाकर शांति, संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया जाएगा।

प्रेस मीट से पूर्व ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व काउंसिल के चेयरमैन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती



ने किया, जो दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन के उत्तराधिकारी हैं। बैठक में देश में शांति, एकता और समावेशी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सूफ़ी परंपरा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रेस को संबोधित करते हुए हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में शांति और राष्ट्रीय एकजुटता की रक्षा केवल सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि धार्मिक नेतृत्व, सिविल सोसायटी, मीडिया और आम

नागरिकों की साझा ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सूफ़ी परंपरा प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देती है, जो सदियों से भारत की बहुलतावादी संस्कृति की आधारशिला रही है और आज भी उग्रवाद के खिलाफ एक सशक्त वैचारिक शक्ति है। उन्होंने दिल्ली में काउंसिल के मुख्यालय की स्थापना को सूफ़ी संस्थानों और दरगाहों की एक साझा राष्ट्रीय आवाज करार दिया। साथ ही कहा कि भारत को आज वैश्विक मंच पर, विशेषकर मुस्लिम देशों में, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता

है। यह भारत में सभी धर्मों और समुदायों को समान सम्मान मिलने का प्रमाण है।

दरगाह फतेहपुरी सीकरी, आगरा के सज्जादा नशीन एवं काउंसिल के उपाध्यक्ष अरशद फरीदी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सूफ़ीवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सूफ़ीवाद प्रेम, शांति, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान का मार्ग दिखाता है, जो समाज में बढ़ती नफरत और विभाजन को समाप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अरशद फरीदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। बांग्लादेश में सूफ़ियों और सूफ़ी परंपरा से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

इस प्रेस मीट में देशभर से आए 25 से अधिक प्रतिष्ठित सज्जादा नशीनों और

सूफ़ी विद्वानों ने भाग लिया और शांति, एकता तथा राष्ट्रीय सौहार्द के लिए अपने सामूहिक संकल्प को दोहराया।

इस मौके पर प्रमुख रूप से हज़रत सैयद फरीद अहमद निज़ामी (दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन), अली शाह (दरगाह कलियार शरीफ), नैयर मियां (दरगाह रादौली शरीफ, उत्तर प्रदेश), डॉ. हबीबुर्रहमान नियाज़ी (दरगाह, जयपुर), मुहम्मद अली (दरगाह अबुल्लाह, आगरा), अली ज़की हुसैनी (दरगाह गुलबर्गा), हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल, गुलाम नज़्मी फारूकी, नेशनल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल शामिल रहे।

कार्यक्रम के अंत में ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल ने मीडिया जगत का आभार व्यक्त करते हुए अपील की कि वह शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के संदेश को समाज तक पहुँचाने में अपनी सकारात्मक और ज़िम्मेदार भूमिका निभाता रहे।

जयपुर मेट्रो की विनम्र अपील, मेट्रो रेल मार्ग में पतंगबाज़ी जानलेवा

जयपुर, (प्रेस विज्ञप्ति) मेट्रो के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ मार्ग में रेल संचालन 25000 वोल्ट बिजली के तारों द्वारा किया जाता है, जिनमें लगातार 24 घंटे करंट चालू रहता है। यह बिजली के तार मेट्रो रूट पर सड़क से करीब 30 मीटर ऊंचाई तक है। यदि पतंग का मांझा इन बिजली के तारों में उलझ जाये तो करंट इस मांझे से सीधे ही पतंग उड़ाने वाले तक पहुँच कर खतरनाक व जानलेवा साबित हो सकता है।

पतंगो एवं मांझे के कारण मेट्रो ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, गत वर्ष मकर संक्रांति की अवधि में ऐसा हो चुका है।

जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री वैभव गालरिया ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए सभी नागरिकों से मेट्रो रेल मार्ग के आसपास पतंगबाज़ी ना करने एवं हर्षोल्लास के साथ सुरक्षित मकर संक्रांति के उत्सव को मनाने की अपील की।



ईरानी नागरिकों से रज़ा पहलवी की अपील- 'दमनकारी शासन के खिलाफ प्रतिरोध जारी रहे'

ईरानी विपक्षी नेता रज़ा पहलवी ने देश की जनता से इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने की अपील की है। उन्होंने दमन और डर के माहौल को खत्म करने के लिए विशेषज्ञों से शासन के सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल करने का आह्वान किया है।

ईरानी विपक्षी नेता रज़ा पहलवी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक संदेश में ईरान के लोगों से दमनकारी शासन का मुकाबला करने और प्रतिरोध जारी रखने की अपील की है। उन्होंने ईरानी सरकार पर आंदोलन को कुचलने के लिए हत्याओं, दमन और



संचार सेवाओं को ठप कर डर फैलाने का आरोप लगाया है।

पहलवी ने प्रदर्शनकारियों की तुलना फारसी पौराणिक कथाओं के पात्रों 'जहक के खिलाफ कावेह' से

करते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि जनता के कड़े विरोध की वजह से हजारों सैन्य और सुरक्षाकर्मी दमन में शामिल होने से बचने के लिए अपनी ड्यूटी पर

नहीं लौट रहे हैं।

इसके साथ ही रज़ा पहलवी इंटरनेट और संचार विशेषज्ञों से खास तौर से गुजारिश की है कि वे शासन के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को बाधित करें, जिससे ईरानी लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क फिर से जुड़ सके।

रज़ा पहलवी ने इंटरनेट और संचार के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से एक खास अपील की है। उन्होंने उनसे शासन के सूचना बुनियादी ढांचे (Information Infrastructure) को टारगेट करने की गुजारिश की है। उनका मानना है कि ऐसा करने से शासन की संचार

शक्ति कमजोर होगी और आम लोगों को इंटरनेट लिंक बहाल करने में मदद मिलेगी, जिससे वे दुनिया को अपनी स्थिति बता सकेंगे।

पहलवी ने अपने संदेश में फारसी तारीख को याद दिलाते हुए प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने इस संघर्ष को अत्याचार के खिलाफ इंसाफ की जंग करार दिया है। उनके मुताबिक, शासन के अंदर भी दरार पैदा हो रही है क्योंकि सुरक्षाकर्मी अब निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे डर की दीवार को गिराकर आजादी की तरफ कदम बढ़ाएं।

US की आजादी के 250 साल

नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका की आजादी के २५० वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों में भारतीय नौसेना का जहाज़ INS सुदर्शिनी भी भाग लेगा। यह भारत-अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा और कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है।

भारतीय नौसेना के अनुसार, INS सुदर्शिनी इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मैत्रीपूर्ण नौसैनिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुद्रिक परंपराओं से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेगा। इस दौरान भारतीय नौसेना की पेशेवर दक्षता, समुद्री विरासत और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

अमेरिकी संसद में आया ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का बिल

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आक्रामक रुख अपना रखा है। ट्रंप के आक्रामक रुख के बीच अब अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का बिल भी आ गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा जाहिर करते रहे हैं। ट्रंप की पार्टी ने अब उनकी इस मंशा को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंडी फाइन ने सोमवार को अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया है। फ्लोरिडा से सांसद रैंडी फाइन ने जो बिल अमेरिकी संसद में पेश किया है, उसे 'ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट' नाम दिया गया है।

ट्रंप की पार्टी के सांसद की ओर से अमेरिकी संसद में पेश किए गए इस बिल में ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेने, भविष्य में अमेरिका का एक राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देता है। इस विधेयक का समर्थन करने वाले लोग आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जरूरी बता रहे हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बिल का कड़ा विरोध हो रहा है और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाएगा कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी



क्षेत्र के रूप में हासिल करने या उस पर बातचीत करने के लिए जो भी कदम जरूरी हों, वह उठा सके। साथ ही, इसमें कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का प्रावधान भी है, जिसमें ग्रीनलैंड को भविष्य में अमेरिका का राज्य बनाने के लिए जरूरी सुधारों का उल्लेख होगा। ट्रंप समर्थक अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक नजरिये से अहम इस द्वीप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बता रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग और मॉस्को के साथ बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में दावा किया कि अमेरिका इस क्षेत्र को हासिल करने के लिए कदम उठा रहा है और यह भी कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने ग्रीनलैंड के लोगों

का जनमत अमेरिका के साथ जाने के पक्ष में तैयार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कदमों पर विचार की बात भी कही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इसे लेन-देन जैसा और अपमानजनक बताते हुए आलोचना की है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने अमेरिकी रुख को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कहना पूरी तरह बेतुका है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन ने अमेरिका की ओर से इस तरह की बयानबाजी को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।

ग्रीनलैंड के एक स्वतंत्रता समर्थक सांसद ने ब्रुसेल्स सिग्नल से कहा कि ग्रीनलैंड के एनेक्सेशन का कोई खतरा नहीं है और अमेरिका के किसी भी दावे का कोई आधार नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने ग्रीनलैंड के जलक्षेत्र में रूसी और चीनी

गतिविधियों की निगरानी में कमी को लेकर चिंताओं को स्वीकार भी किया।

यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोगों के हाथ में है और सहयोगियों को संप्रभु सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और फ्रांस के नेताओं ने दोहराया कि ग्रीनलैंड किसी विजय के लिए नहीं है और उसके भविष्य पर निर्णय केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही ले सकते हैं।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने चेतावनी दी कि आर्कटिक नीति सहित ट्रांस-अटलांटिक मतभेद यूरोपीय एकता को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के दौर में सामूहिक रक्षा और कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्रीनलैंड की आबादी करीब ५५ हजार है। इस आबादी में अधिकतर लोग स्वदेशी समुदाय से हैं, जो कई सर्वेक्षणों के मुताबिक अमेरिका का हिस्सा बनने का भारी विरोध करता है। डेनमार्क से स्वतंत्रता को लेकर ग्रीनलैंड में लंबे समय से चल रही मुहिम अमेरिकी कवायदों को और जटिल बना सकती हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक रुचि का एक बड़ा कारण रूसी नौसैनिक गतिविधियों के साथ ही आर्कटिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता चीनी निवेश भी है।

NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

Sharia, Manusmriti or Indian Constitution



Prof. Ram Puniani

The Indian Constitution has been the outcome of the values which emerged during our freedom struggle. The Constituent Assembly, broadly a representative of India, formulated the Indian Constitution which as a whole is the guide to our national life.

The Constitution calls for democratic society based on Liberty, Equality, Fraternity and Social justice.

There was a section of political opinion mainly formed by conservative Hindus and those arguing that India should become a Hindu nation; who opposed it right from the start.

The leaders of Hindu nationalist politics, supported by the conservative sections of society's opinion; was articulated by an article in *Organiser*, the RSS mouthpiece, which opposed the Indian Constitution; saying that there is nothing Indian about it and it will not be accepted by the Hindus. Savarkar, went on to say that *Manu smriti* is the Constitution today.

In this spirit Swami Avimukteshwaranand recently stated that *Manu smriti* is above the Indian Constitution.

This stream is not the only one to undermine the constitution and showing the primacy of 'word of God' or sacred scriptures. Maulana Mufti Shamail Nadwi made a similar statement.

This Maulana has come to prominence in the last few days after his debate with Javed

Akhtar on "Does God exists". In a viral clip, he asserts that "Muslims erred by accepting secularism and the supremacy of national institutions over Shariah, criticizing democracy and the notion of placing the nation (desh) above religion."

He questions whether believers should passively accept court verdicts conflicting with Islamic law. These statements, while presented as theological opinions, have been interpreted by critics as undermining India's constitutional secularism and promoting religious supremacy."

While *Manu smriti* is a compilation representing the values of Brahmanism, the dominant stream within Hinduism, Sharia is based on multiple things. Sharia (Arabic: the path) is the Islamic legal-ethical system derived from:

"Qur'an, Hadith (sayings/actions of Prophet Muhammad), Ijma (consensus of scholars) and Qiyas (analogy)" It guides personal conduct and law, not just punishments. In practice, Sharia is interpreted through schools of jurisprudence (Sunni: Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali; Shia: Ja'fari), so there is a diversity within the legal system of Sharia.

Out of nearly 55 Muslim majority countries it shapes the laws etc. only in Saudi Arabia, Iran and Afghanistan fully. Partly it is implemented in a few other Muslim majority countries. In India it forms a base in matters of Muslim personal laws only.

So, what does one do with changing times and the social patterns, which have occurred over a period of centuries when these laws were devised. Those doing politics in the name of religion in India harp on bringing in *Manu smriti* and countries like Iran, Afghanistan and Saudi Arabia are having sharia in full. In many Muslim countries it is not implemented or implemented only in part.

Can Sharia be above the Constitution as the Mufti claims?

The legal luminary Faizan Mustafa in a video https://chatgpt.com/s/t_6958cc1175d881918e5e6573c342c651 argues that in every country the Constitution is supreme. The Constitution does consider Sharia in many countries and integrates some aspects of that in the Constitutions.

So, what is the status of democratic institutions in Muslim majority countries? There are different degrees of 'democracy' in these countries. At the moment many social sites are criticizing Shamail for encouraging Muslims not to follow the constitution, which is an anti-patriotic act.

On the other hand, many are praising the Mufti for upholding the Sharia. It is interesting to note that during the medieval period of Indian History, the Muslim Kings did not make it obligatory for the state.

While Mufti Shamail has one opinion there are others like Asghar Ali Engineer, the foremost scholar of Islam in India; who have different idea about the role of Sharia vis a vis Constitution.

Dr. Engineer harps on Shura (Mutual consultation); to argue that democracy and related principles are possible in the contemporary World. Dr. Engineer says a Quranic concept – and modern-day representative democracy – merely a human concept – may not be exactly similar. However, "the spirit of modern democracy and the Qur'anic injunction to consult people is the same".

As per him "New institutions keep on developing and human beings, depending on their worldly experiences, keep on changing and refining these institutions. And in the contemporary world, the concept of Shura should mean democratic process and constitution of proper democratic institutions of which elections are a necessary requirement."

The Qur'anic text not only gives the concept of Shura (democratic consultation) but

"does not support even remotely any concept of dictatorship or authoritarianism".

In India's freedom struggle, which was based on democratic principles and aimed at democratic institutions; very tall Islamic scholar Maulana Abul Kalam Azad and a dedicated Muslim leader Khan Abdl Gaffar Khan (to name the few) strove for the values and institutions of democratic secular country.

Just a few years ago the Muslim women through the Shaheen baug movement showed their democratic strength in protecting the community from the fear of disenfranchisement.

What is needed in contemporary times? In India as Muslims are being targeted by Hindutva politics, they have become a besieged community. The conservatism among Muslim community is rising. The major issue confronting them is to save their rights as citizens using modern institutions.

Even in Islam there are various streams of laws and systems of jurisprudence. Since this is part of Sharia, in that case what Sharia recommends will be another contentious issue. Since Muslims are a minority in this country, they already have Personal laws, which are again under opposition.

Today Hindu right wing is the dominant retrograde tendency trying to bring to fore the values of *Manu smriti*. Such assertions which want to bring inequality in the garb of religion are not welcome. We need to also look to some European countries where religion is on the backfoot.

We are living in contradictory times. On one side human society has developed the principles of dignity and equality as represented in the UN charter and on the other religious rightwing has become stronger during the last few decades. While Mufti is knowledgeable in concepts of Islam, we also need to know what are the trends of contemporary society and values of democratic institutions.

When Faith Prevails Beyond Reason



Najmuddin Farooqui

The long-standing and often circular debate over the scientific evidence for the existence of God may, from a strictly intellectual standpoint, appear to yield no definitive conclusion. Yet such debates are rarely remembered for their logical outcomes alone. Sometimes, their true significance lies in the social, psychological and spiritual responses they evoke. One such debate conducted between an Islamic cleric and a self-proclaimed disbeliever stands out precisely for this reason. Ironically, it unfolded as one of the most secular discussions within a deeply non-secular environment. Broadcast live and watched by

millions online, it became one of the most viewed programs on YouTube within a short span of time. While some observers regarded it as an exercise in futility particularly for viewers who invested nearly two hours listening to familiar arguments it nevertheless proved to be an engaging and absorbing public spectacle. The Islamic scholar, a relatively unknown figure before the event, appeared well-prepared and deeply motivated by his faith and devotion to Allah. His objective was not merely to defend belief, but to inspire and instil faith in his audience. The aftermath of the debate was telling, the cleric emerged as a widely recognised public figure, sought after by media outlets and embraced by the Muslim masses, while his already well-known opponent remained where he was unchanged in stature or influence. From a critical perspective, a person who professes no faith has little need to promote disbelief unless driven by a desire to advance scientific temperament, particularly among the youth. Such advocacy is often linked to aspirations for material progress and success in a modern, materialistic world. There is nothing inherently wrong with this pursuit; material success is a legitimate as-

piration and a right for everyone, including Muslims. However, human life cannot be reduced solely to material achievement. Faith in the existence of God becomes indispensable precisely at the point where logic, reason and scientific explanation reach their limits. In a world of nearly eight billion people, those who identify as having “no faith” constitute a relatively small minority. While it is impossible to quantify faith or measure the depth of one’s belief or love for God, it is evident that a vast majority of people, even while striving for worldly success, quietly seek divine help and reassurance. Those who love God purely for spiritual fulfilment and the hope of a better hereafter may indeed form a small minority, but their presence underscores an essential truth faith serves purposes beyond measurable outcomes. Notably, belief in God is not confined to religious communities alone. A significant number of scientists and more strikingly, medical professionals despite practising evidence-based medicine, often encourage patients to pray for health and recovery. This reflects an implicit recognition that healing is not purely mechanical and that the human

mind and spirit play vital roles in recovery. Religious individuals, by and large, tend to display greater emotional and psychological resilience. They are often less stressed, more disciplined and better able to cope with adversity, even in conditions of limited resources or wealth. Statistically, they exhibit lower rates of suicide and severe mental breakdowns, and they often report greater inner peace and better sleep. Modern medical science itself acknowledges its limitations. Despite remarkable advances, the human brain remains one of the greatest frontiers of scientific inquiry. Neuroscience has yet to fully understand the intricate network of approximately 86 billion neurons and their hundreds of trillions of connections. Until this mystery is unravelled, claims of complete understanding of human consciousness, belief and faith remain premature. In this space of uncertainty where science pauses and wisdom humbly admits its limits faith continues to endure, heal and guide. Submission, it seems, does not weaken humanity rather it sustains it.

From Strategy to Partnership

India–Germany Ties Take Shape

In a rapidly changing and increasingly complex world marked by conflicts, contradictions and strategic rivalries, countries are being compelled to chart new and independent paths. Focusing on cooperation rather than confrontation remains the most effective way to avoid conflicts. In today’s global environment, deeper engagement is required across defence, technology, energy, science and research, trade and innovation. Against this backdrop, India and Germany are steadily strengthening their bilateral relationship. India was among the first countries to formally recognise Germany after the Second

World War. Diplomatic relations between the two nations were officially established on March 7, 1951, and this year marks 75 years of those ties. The milestone comes at a significant moment, as German Chancellor Friedrich Merz is on his first official visit to India. Chancellor Merz’s visit assumes particular importance at a time when trade-related tensions persist between India and the United States. Notably, India was chosen for his first Asia tour as Chancellor, breaking a long-standing tradition in which German leaders typically visited China or Japan. This

shift underscores India’s growing strategic importance in Germany’s foreign policy calculations. The warmth of the relationship was on display at Ahmedabad’s Sabarmati Riverfront, where Chancellor Merz joined Prime Minister Narendra Modi at the International Kite Festival, symbolising the rising trajectory of India–Germany ties. Substantive discussions followed at Mahatma Mandir in Gandhinagar, where the two leaders oversaw the signing of 19 agreements spanning semiconductors, critical minerals, free transit visas, defence, space

cooperation, renewable energy and environmental protection. Germany is India’s largest trading partner within the European Union, with bilateral trade in goods and services reaching significant levels in 2024–25. Chancellor Merz’s visit is also being viewed as the beginning of a deeper and long-term engagement between India and the European Union. This is further reflected in the upcoming visits of European Union leaders for India’s Republic Day celebrations, followed by the visit of French President Emmanuel Macron to New Delhi for the Artificial Intelligence Impact Summit.

AMU Donor Writes to Union Education Minister Alleging Religious Harassment of Hindu Woman Professor

New Delhi : An alumnus and donor of Aligarh Muslim University (AMU), Prof. Jasim Mohammad, has written a letter to Union Education Minister Dharmendra Pradhan, raising serious concerns over the alleged harassment and institutional marginalisation of a senior hindu woman professor, Prof. Rachana Kaushal, and accusing the university’s top leadership of “grave administrative abdication and moral collapse.”

In the letter, Prof. Jasim Mohammad, has directly named AMU Vice-Chancellor Naima Khatoon, holding her responsible for failing to act on a formal complaint submitted in September 2025 by Prof. Kaushal. He alleges that despite the seriousness of the allegations—ranging from denial of statutory rights and professional humiliation to exclusion from academic bodies



and communal prejudice—the university administration remained silent and attempted to bury the issue, thereby damaging the credibility and public image of Aligarh Muslim University. Referring specifically to Prof. Rachana Kaushal’s complaint September 2025, the alumnus describes it as emblematic of a deeper rot within the university. According to the letter, the complaint details deliberate

professional marginalisation, denial of statutory entitlements, sustained humiliation, and communal targeting—charges serious enough, he argues, to warrant immediate intervention and an independent inquiry. “The Vice-Chancellor did none of this,” the letter notes, adding that inaction has emboldened misconduct rather than curbed it. The letter further argues that such matters should have been

resolved internally through transparent and fair academic processes. Placing the issue in a wider context, Prof. Jasim Mohammad states that since June 2017—and with increasing intensity in recent years—AMU has become an environment marked by fear, anxiety, and psychological trauma for both teachers, employees and students. “In such an atmosphere, how can the ideals of the National Education Policy (NEP) 2020 be realised?” the letter asks, warning that an institution paralysed by mistrust cannot educate a confident and innovative generation. He has urged the Ministry of Education to constitute a high-level, independent committee to examine governance failures at AMU, with a specific mandate to assess fear, anxiety, and institutional trust on campus.

SUBSCRIPTION FORM

TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF

TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:
Language: English, Hindi and Urdu
Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W
No. of Pages: 12 pages (more in future)
Price: Rs. 3/-
Print order: 25,000
Periodicity: Weekly
Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.
Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page
Please Add Rs. 10 for outstation cheques.
50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc.
(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

दलिया या उपमा, नाश्ते में क्या खाना ज्यादा हेल्दी है

दलिया को टूटे हुए गेहूं भी कहा जाता है। यह फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। वहीं, सूजी (रवा) से बनने वाला उपमा जल्दी पच जाता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। आज हम इस खबर में जानेंगे कि वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाना बेहतर रहेगा और क्यों।

भारतीय घरों में नाश्ते के लिए दलिया और उपमा दोनों ही खूब पसंद किए जाते हैं। दलिया मोटे पिसे हुए गेहूं से बनता है, जबकि उपमा सूजी यानी रिफाइंड गेहूं से तैयार किया जाता है। दोनों ही हल्के होते हैं, लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं और आसानी से बन जाते हैं। लेकिन वजन कम करने वालों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि इन दोनों



में से कौन ज्यादा बेहतर है।

दलिया फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है। यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। वहीं उपमा जल्दी पच जाता है। इससे शरीर को तुरंत एनर्जी तो मिलती है लेकिन यह दलिया की तुलना में कम समय तक पेट को भरा रखता है। इसलिए वजन घटाने के लिए दलिया थोड़ा बेहतर

ऑप्शन माना जाता है।

एक कटोरी पके हुए दलिया में लगभग 150-180 कैलोरी होती हैं जो इसे हल्का और कम फैट वाला बनाती हैं। इसलिए इसे वजन कम करने वालों के लिए हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। वहीं एक कटोरी उपमा में लगभग 200-220 कैलोरी होती हैं, खासकर तब जब इसे तेल, घी या काजू डालकर बनाया जाता है। उपमा हेल्दी जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा कैलोरी होती है।

दलिया में प्रोटीन और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं जो वजन घटाने के लिए जरूरी हैं। उपमा में कुछ बी विटामिन होते हैं और अगर इसमें ढेर सारी सब्जियां मिलाई जाएं तो यह और भी हेल्दी बन सकता है। लेकिन बिना सब्जियों के इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा दलिया से कम होती है।

जो लोग अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके लिए दलिया बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, कैलोरी कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है। वहीं, उपमा भी और हेल्दी बन सकता है अगर इसे कम तेल में और ज्यादा सब्जियां डालकर बनाया जाए।

सर्दियों में घुटनों-कमर-कंधों का दर्द नहीं करेगा परेशान

सर्दियों में जोड़ों का दर्द, अकड़न और सूजन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इससे छुटकारा दिलाने का काम तेल मालिश कर सकती है। सवाल ये है कि किन तेलों से मालिश करनी चाहिए। आज हम आपको दादी-नानी के बताए असरदार मसाज ऑयल बताएंगे, जो दर्द से राहत दिलाएंगे।

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ शरीर के अंदर हार्मोस बदलते हैं, वहीं दूसरी ओर हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। बढ़ती उम्र में होने वाले बदलावों का सबसे ज्यादा असर हमारे जोड़ों पर पड़ता है। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर अकड़ जाना तो कभी कंधों में जकड़न ये सभी बढ़ती उम्र में बहुत ही आम माने जाते हैं।

दरअसल, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और जोड़ों के बीच की चिकनाहट (कार्टिलेज) कम होने लगती है। इसी वजह से सूजन, अकड़न और दर्द की परेशानी शुरू हो जाती है। गौर करें तो आजकल ना केवल घर के बड़े बुजुर्ग बल्कि कम उम्र के लोग भी जोड़ों में दर्द की शिकायत करते नजर आते हैं। सर्दियों में ये समस्या दोगुनी हो जाती है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि थोड़ी-सी देखभाल और कुछ आसान आदतों को अपनाकर जोड़ों के दर्द से



काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। इनमें से एक दादी-नानी के समय से चलती आ रही है। वो क्या है? तो बता दे, वो तेल मालिश है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से तेल हैं जिनसे मालिश करके आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं? चलिए जानते हैं।

बढ़ती उम्र में जोड़ों के बीच मौजूद तरल पदार्थ कम होने लगता है, कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगता है, लिगामेंट्स सख्त हो जाते हैं और मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं। इन सब वजहों से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और दर्द, सूजन और जकड़न की समस्या होने लगती है। आजकल के बिगड़े खानपान और लाइफस्टाइल के चलते छोटी उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है।

आपने अक्सर अपनी दादी-

नानी को अपने हाथों-पैरों में तेल मालिश करते देखा होगा। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि नियमित रूप से जोड़ों में तेल से मालिश करने से अकड़न कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। अगर तेल सही हो तो आराम दोगुना हो जाता है।

कभी भी एसेंशियल ऑयल सीधे स्किन पर ना लगाएं, इससे जलन हो सकती है। हमेशा किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल, बादाम या जोजोबा ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें।

इस लगाने का एक आसान तरीका ये है कि 6 चम्मच कैरियर ऑयल में 15 बूंद एसेंशियल ऑयल मिलाएं। तेल को हल्के हाथों से दर्द वाली जगह पर लगाएं और ऊपर से गर्म कपड़ा ओढ़ लें।

उम्र चाहे जो भी हो, अगर अपनी रोजाना की लाइफस्टाइल

सही रखी जाए तो जोड़ों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है।

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, योग या स्ट्रेचिंग से मसल्स मजबूत रहती हैं और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। इससे जोड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।

वजन बढ़ने से घुटनों और कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। बाँड़ी फैट जोड़ों के आसपास सूजन बढ़ाने वाले तत्व भी छोड़ती है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है।

सही खान-पान न सिर्फ वजन कंट्रोल में रखता है बल्कि शरीर में सूजन को भी कम करता है। हरी सब्जियां, फल, नट्स और हेल्दी फैट जोड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही घरेलू मसाज ऑयल से मालिश करने से भी आराम मिलता है।

खेल समाचार

WPL के मैच बिना दर्शकों के, नगर निगम चुनाव बने वजह



महिला प्रीमियर लीग (WPL) को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। नवी मुंबई नगर निगम चुनावों के चलते 14 और 15 जनवरी को होने वाले WPL मुकाबले दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। ESPN Cricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के कारण पुलिस ने इन मैचों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

पुलिस ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सूचित किया है कि 15 जनवरी को मतदान होने के कारण सुरक्षा बलों की तैनाती चुनावी ड्यूटी में रहेगी, ऐसे में स्टेडियम में दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा। इसी कारण इन मुकाबलों को बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

जिन मैचों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, उनमें 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स और 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स का मुकाबला शामिल है। वहीं, 16 जनवरी को होने वाले गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस तारीख के लिए दर्शकों के प्रवेश को लेकर बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

WPL के आधिकारिक

टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर 14, 15 और 16 जनवरी के मुकाबलों के टिकट फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। इससे संकेत मिलता है कि इन तारीखों के लिए दर्शक प्रतिबंध अभी लागू रह सकते हैं, हालांकि अंतिम फैसला बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

गौरतलब है कि WPL का शेड्यूल 29 नवंबर को जारी किया गया था, जबकि नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा 15 दिसंबर को हुई। चुनाव की जानकारी मिलने के बाद WPL समिति को अवगत कराया गया था, लेकिन तब तक नवी मुंबई में होने वाले मैचों की लॉजिस्टिक तैयारियों में बदलाव करना संभव नहीं रह गया।

17 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले डबल-हेडर मुकाबलों के टिकट फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस दिन पहले मैच में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स आमने-सामने होंगी, जबकि दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दर्शकों के साथ सामान्य व्यवस्था बहाल हो जाएगी।

17 जनवरी के मुकाबलों के बाद WPL का आगे का सफर वडोदरा में जारी रहेगा, जहां टूर्नामेंट के शेष मैच खेले जाएंगे।

یمن پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی

اسد مرزا

ایک وقت تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ملحق خطے میں علاقائی سلامتی کے جڑواں ستون سمجھے جاتے تھے، لیکن آج متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور سعودی عرب دونوں یمن میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ جمعے کے روز، متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورس نے اعلان کیا کہ ”جنگ“ شروع ہو چکی ہے اور سعودی حمایت یافتہ زمینی افواج پر سعودی فضائیہ کے فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے یمن کے جنوبی دھڑوں کو ریاض میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے بلایا ہے، جب کہ جنوب میں واقعات کے ڈرامائی موڑ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو غیر معمولی براہ راست تصادم پر لا کھڑا کیا ہے۔ دونوں جنگی طاقتوں نے ملک کی طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی جانب سے مداخلت کی ہے، لیکن اتحاد کی ٹوٹ پھوٹ نے انہیں زمین پر مختلف حریف گروپوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک گروپ اب جنوبی یمن میں ایک الگ ہونے والی ریاست کی آزادی کا اعلان کرنے پر زور دے رہا ہے۔ سعودی وزارت نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں ”ریاض میں ایک جامع کانفرنس پر زور دیا کہ تمام جنوبی دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ جنوبی کاز کے مضامین پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔“ ریاض نے کہا کہ یہی حکومت نے مذاکرات کی دعوت جاری کی ہے۔ یمن کی خانہ جنگی 2014 میں شروع ہوئی تھی اور اس نے پہلے سے ہی غریب ملک کو کئی سالوں کے مہلک تشدد اور دنیا کے بدترین بھوکے بچوں میں ڈال دیا ہے۔ جنگ کے آغاز میں، ایران کی حمایت یافتہ باغی حوثی تحریک نے دارالحکومت صنعاء سمیت شمالی یمن کے بیشتر حصے پر حکومت سے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یہ تنازعہ

2015 میں بڑھ گیا، جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت عرب ریاستوں کے اتحاد نے حکومت کی بحالی کے لیے فوجی مہم شروع کی۔ جنگ بندی نے حالیہ برسوں میں حوثیوں کے ساتھ تنازعہ کو کم کیا ہے اور اگلے مہینوں کو ختم کر دیا ہے لیکن سعودی حمایت یافتہ حکمران اتحاد۔ (PLC)، جو 2022 میں تشکیل دیا گیا تھا اور مختلف حوثی مخالف دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ میدان میں اتر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، جنوبی یمن کی اکثریت کو متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں، جنوبی عبوری کونسل (STC) نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو مضابطہ طور پر اتحاد کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کا مرکز جنوبی عبوری کونسل (STC) ہے، جو جنوبی یمن کا سب سے طاقتور گروپ ہے اور جو یمن کی صدارتی کونسل سے بھی متصادم ہے۔ یہ اپریل 2017 میں ان گروپوں کے لیے ایک عبوری تنظیم کے طور پر قائم کیا گیا تھا جو جنوبی یمن کو ایک آزاد ریاست کے طور پر بحال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہ 1967 اور 1990 کے درمیان تھا۔ اب وہ جنوبی یمن کے تقریباً تمام سابقہ علاقے پر کنٹرول رکھتے ہیں، جب کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی شمالی یمن میں طاقت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ STC، جسے مبینہ طور پر UAE کی حمایت حاصل ہے، عدن سمیت جنوب میں اہم علاقے کو کنٹرول کرتا ہے، اور مسلح افواج کی کمانڈ کرتا ہے جسے جنوبی مسلح افواج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حال ہی میں، STC فورسز نے حضرموت کی طرف مارچ کیا اور حکومتی افواج اور ان کے قبائلی اتحادیوں کے ساتھ مختصر جھڑپوں کے بعد یمن کی سب سے بڑی تیل کمپنی بیڑو میسلا سمیت صوبے کی اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب سعودی حمایت یافتہ حضرموت قبائلی اتحاد نے نومبر کے آخر میں بیڑو میسلا تیل کی سہولت پر

نے یمن میں بہت سی مفروضہ معاملات پر اپنا ایک طرف موقف اختیار کیا ہے۔ جس کے نتیجے میں یمن کی بندرگاہ مکملہ پر سعودی عرب نے یو اے ای سے بھیجی جانے والی فوج کی گاڑیوں پر بمباری کی گئی۔ ریاض نے واضح طور پر کہا کہ گاڑیاں ایس نی سی کے استعمال کے لیے بھیجی گئی تھیں اور وہ اماراتی بندرگاہ سے آئی تھیں۔ لیکن اس پورے قیسے میں جو سب سے حیران کن بات ہوئی ہے وہ ہے تازہ ترین متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان کشیدہ تعلقات۔



تو کیا وجہ ہے کہ دونوں ممالک، جو کہ وسیع تر مغربی ایشیا کے علاقے میں بہت سے معاملات پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آج وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ دراصل ہر مسئلے کے پس پشت دو فریقین کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی اصل وجہ اقتصادی ہو رہی ہے۔ تاریخی طور پر، جیسے ان دونوں ممالک کے تعلقات ان کے قائدین محمد بن زائد (MBZ) اور محمد بن سلمان (MBS) کے درمیان برادرانہ تعلقات پر مبنی تھے۔ ایم بی زیڈ جو کہ شہزادہ سلمان کے عمر میں تقریباً ۲۵ سال بڑے ہیں، انہوں نے شہزادہ سلمان کو قومی معیشت کو فروغ دینے

کنٹرول سنبھال لیا۔ عدن میں، متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورس نے صدارتی محل پر بھی قبضہ کر لیا، جو حکمران صدارتی کونسل کی نشست کے طور پر کام کرتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ یمن کو اپنے دست نگر کے طور پر دیکھا، پہلے 2015 میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو شمال میں بہت زیادہ تنقیدی بمباری کی مہم کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی اور پھر بین الاقوامی دباؤ کے تحت حوثیوں کو عدن میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے سفارت کاری کی طرف لوٹا۔ لیکن گزشتہ مہینے میں، متحدہ عرب امارات

اور سرمایہ کاری کے ذریعہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے گر سکھائے۔ اگر آپ دونوں ممالک کے درمیان ایک متوازی جائزہ کریں تو یہ صاف ظاہر ہوگا کہ ۱۹۷۰ کے بعد سے ایم بی زیڈ نے جو کہ اس وقت ابوظہبی کے ولی عہد تھے انہوں نے شیخ محمد بن راشد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو علاقائی سطح پر ایک کاروباری مرکز، بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کا گڑھ اور جدید ٹیکنالوجی کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت تک سعودی عرب اپنی پرانی روش پر قائم تھا اور تیل فروخت کرنے کے علاوہ مذہبی سیاحت کے ذریعہ اپنی معیشت کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن شہزادہ سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد اور خاص طور سے جب سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز علیلیں ہوئے ہیں، تب سے ملک کی معیشت اور اس کے فروغ کی ذمہ داری ایم بی ایس کو پوری طرح حاصل ہو چکی ہے۔ تب سے اب تک انہوں نے کئی نئے منصوبوں کے ساتھ ملک کی معیشت کو ایک نئی راہ پر لے جانے کی شروعات کی تھی اور اس دور میں ایم بی زیڈ نے ان کی رہنمائی بطور ایک سرپرست یا بڑے بھائی کی تھی۔ لیکن سعودی حکام کا ہمیشہ سے یہ زعم رہا ہے کہ چون کہ سعودی عرب کا حجم دیگر علاقائی ممالک سے زیادہ ہے، اس لئے علاقائی دفاعی اور عسکری مسائل پر اس کی رہنمائی پر قرار رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں اس نے تجارتی اور معاشی سطح پر یو اے ای کی طرز پر اپنے شہروں کو فروغ دینا بھی شروع کر دیا۔ دوسری جانب یو اے ای نے اس درمیان میں اپنی دفاعی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے خود کو علاقائی دفاعی رہنما کے طور پر پیش کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے کچھ نقل بھی کیا اور ایک دوسرے کو کچھ دیا بھی لیکن فی الوقت دونوں ہی اپنے آپ کو علاقائی لیڈر کے طور پر تسلیم کرانے کی مہم میں مصروف ہیں اور جو کچھ بھی یمن میں ہو رہا ہے وہ انہی خواہشات کا حصہ ہے۔

وینزویلا حملے سے طاق پروتانون!

وینزویلا شیلی چیزوں سے وابستہ اسمگلنگ سے دہشت گردی کو بڑھا دے رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طاقتور دیش اس طرح کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے کسی چھوٹے ملک کو اور کمزور مملکت پر حملہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی امریکہ جب وہاں کے صدر ٹرمپ دینا کے مختلف ملکوں میں جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے۔ اب انہوں نے خود ہی بیک ڈور سے وینزویلا پر حملہ کر دیا۔ دراصل امریکی پالیسی کسی ملک کو ترقی کرنا نہیں دیکھ سکتی اور وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس سے کمزور کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ اب وینزویلا کے بعد امریکہ ایران میں راج شاہی کو ختم کرنے کے لئے وہاں کے حکومت مخالف لوگوں کو حکمران سرکار کے خلاف شہ دے کر بھڑکا رہا ہے۔ اب جہاں

الاقوامی قانون سے متعلق سوالات اپنی جگہ ہی ہیں لیکن امریکہ کو مداخلت کا موقع دینے کے لئے مادورو کی پالیسیاں ہی ذمہ دار ہیں۔ دراصل وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے۔ وہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کچھ عرصہ سے چلے آ رہے آج ہی تنازعات کا نتیجہ ہے۔ جواب خوفناک شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ وینزویلا کی راجدھانی قراقرص میں جمع کی دہررات امریکی ہوائی جہازوں کے حملوں سے دہل اٹھی اور اس کارروائی کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ صدر نکولس مادورو اور ان کی بیوی کو حراست میں لے کر دیش سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اس حملے کی وجہ منشیات چیزوں کی اسمگلنگ بتائی جاتی ہے۔ امریکہ کا الزام ہے

وینزویلا میں نکولس مادورو سرکار کا تختہ پلٹ کر امریکہ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جس وجہ سے ملک میں سیاسی سطح پر قتل پھیل رہی۔ موجودہ صدر نکولس مادورو کے دورہ عہد میں کراس گھر ابو گیا اور امریکہ جیسے ملکوں کی پابندیوں نے حالات کو اور مزید مشکل بنا دیا جس سے ملک میں وینزویلا میں کشیدگی کی انتہا کو پہنچ گئی اور اس کی وجہ سے تقریباً 82 فیصد ملک کے باشندے غریبی میں جی رہے ہیں۔ جس وجہ سے ان لوگوں کو اپنی روزمرہ کی کھانے پینے تک کی چیزیں بھی میسر نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہاں مہنگائی زیادہ ہے جس وجہ سے ملک میں فاقہ کشی بیماری اور کرائم شرح بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ زندگی کی گزربسر کے لئے 80 لاکھ شہری وینزویلا سے ہجرت کر چکے ہیں جس وجہ سے وہاں بڑی مشکل آکھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ نے جس طرح سے وینزویلا میں فوجی کارروائی کر کے وہاں کے صدر کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے وابستہ سفارتی سیاسی اور بین

اندور میں آلودہ پانی سے اموات کی ٹریجڈی!

81 فیصد علاقوں میں پانی کی ٹوٹی سے پہنچانے کا دعویٰ ابھی تک کھوکھلا ہی ثابت نظر آتا ہے۔ لیکن اس مشن کو ایمانداری سے عمل میں لانا ہے تو پانی سپلائی انٹرکچر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو 2047 تک وکست دیش کی قطار میں کھڑا ہونے کا نشانہ طے کیا ہے۔ لیکن عام لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو اس مشن کو پانے کے لئے پورا کرنا ہوگا۔ اور 2050 تک بھارت ک آبادی ایک عرب 70 کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے اور موجودہ پانی وسائل آج کی آبادی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پارے ہیں اس لئے آنے والے سالوں میں پانی میٹورک میں بہتری کی ضرورت ہے، آج بھی ہمارے دیش کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو کچا پانی یا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کیوں کہ سرکاری مشینری ابھی تک ان دیہاتوں میں پینے کے پانی کی لائن بچھانے کے نشانہ کو پورا نہیں کر پارہی ہے۔ اس لئے مودی جی باتیں تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے محل جیون مشن پر کتنا کام ہوا ہے اس پر بھی دھیان دیا ہے۔

پارٹی کی سرکار ہوتی اور مدھیہ پردیش میں موجودہ حکمران بھاجپا سرکار معاملہ کو لے کر آسمان سر پر اٹھالیتی۔ بھاجپا کے ورکرز لوگوں پر اثر آتے لیکن مدھیہ پردیش میں گٹر ملا پانی پینے سے کثیر مقوتوں پر مودی سرکار خاموش کیوں ہے اس نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کو بلا کر معاملہ کی سچائی کیوں نہیں جانی اور مرے لوگوں کے درثناء آنسو تک پونچھنے کی ضرورت تک نہیں سمجھی۔ لوگوں کا الزام ہے شکایتوں کے باوجود اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے تب جا کر معاملہ ریاستی ہائی کورٹ میں گیا۔ اور اس کی مداخلت کے بعد ریاستی حکومت آلودہ پانی سے ہوئی اموات کو گچھانے کی کوشش میں لگ گئی ہے۔ یہ انتہائی شرمناک قدم ہے۔ بھالیرتھ پورہ کا واقعہ شہری سہولیات کی کمی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے آج بھی دیش میں ہر ایک لاکھ آبادی آلودہ پانی پینے سے او۔سطاً 35 لوگوں کی جان جاتی ہے۔ گولڈی پورج کے مطابق مقابلوں میں یہ تین گنا ہے۔ بیشک سرکار نے محل جیون مشن جیسی پانی سپلائی مہم چلائی جس کی بدولت

افسران کو معطل اور ایک کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ہوریہ چانچ سے پتہ چلا ہے کہ نرمدا محل لائن کے اوپر اور آس پاس ڈریج جیبر بنے ہوئے تھے۔ اس سے گزر رہی لائنوں میں پانی جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ ایک پولیس چوکی کا ٹوائلٹ بھی اس پائپ لائن کے اوپر بنایا گیا۔ جس سے نکلنے والا شہر تچ سید ہے ان پائپ لائنوں میں سوراخوں میں پانی جا رہا تھا۔ اس ٹریجڈی سے ہائے توبہ بچی تو ریاستی حکومت نے سٹی میونسپل کمشنر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ مدھیہ پردیش میں بھاجپا سرکار ہے نے واقعہ کی لپٹا پو پتی اور معاملہ کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اسی کڑی میں پانی سپلائی انچارج و ایگزیکٹو انجینیر سے ڈریج ٹمک کی ذمہ داری واپس لے لی ہے۔ کیا انتہائی کافی ہے۔ کسی افسر کو سزا دینے کے لئے اس طرح کی روزمرہ کی کارروائی ذمہ داروں کو سبق نہیں دیتی بلکہ متاثرین کا مذاق بناتی ہے۔ یہاں اوپر سے نیچے تک سبھی افسران اور ان کے ماتحت عملہ کی جوابدہی ہے۔ اگر مدھیہ پردیش میں کسی اپوزیشن

دیش کے صاف شہر اندور کے بھالیرتھ پورہ علاقہ میں آلودہ پانی پینے سے پھیلا کر آس کوئی ایک دن کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں مسلسل لا پرواہی اور خراب پڑی پانی کی لائیں اور ان کی نگرانی میں کمی کا نتیجہ ہے۔ چھ دن میں 17 لوگوں کی موت سے شہر کے آئی نظام سپلائی کی خوفناک تصویر سامنے آئی ہے۔ دراصل رہواسی کئی ہفتوں سے گندے پانی آنے کی شکایت کر رہے تھے لیکن مقامی انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جس سے 29 دسمبر 2025 کو حالات اس وقت بگڑے جب 100 سے زیادہ لوگوں کو اٹنی اور دست آنے لگے۔ اور اگلے دن حالات اور بگڑ گئے جس کے نتیجہ میں 8 ریسٹورن کی ایک کے بعد ایک موت ہوئی چلی گئی۔ لیکن اب تک 17 سے زیادہ لوگوں کی موت کی بات سامنے آئی ہے۔ اب تک 1200 لوگ آلودہ پانی پینے سے بیمار ہیں۔ جن کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ سٹی میونسپل کارپوریشن نے آنا فانا میں پانی کے کنٹینر چانچ کے لئے بھیجے ہیں اور انتظامی کارروائی میں دو

Qatar Ambassador highlights cultural partnership at New Delhi World Book Fair

NEW DELHI: The Ambassador of the State of Qatar expressed delight at addressing the press ahead of the opening of the New Delhi World Book Fair, describing it as one of the region’s leading cultural platforms and emphasizing Qatar’s strong belief in the role of culture and knowledge in building bridges of understanding among peoples.

Speaking at the press conference, the Ambassador said Qatar’s participation as Guest of Honour at this year’s Fair underlines its ongoing commitment to promoting cultural and intellectual dialogue and strengthening knowl-



edge exchange between the Arab world and India, both home to civilizations rich in history,

heritage and diversity.

He recalled that Qatar’s participation in last year’s edition of the Fair included the launch of the Malayalam-language book “As Seen, Read and Lived, Qatar Through My Eyes: History, People and Sovereigns” by His Excellency Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani. He described this as an important cultural milestone that reflected the depth of cultural ties and Qatar’s dedication to reaching readers across languages and cultures.

The Ambassador also cited the recent launch of “The Doha Historical Dictionary of Arabic” as a landmark scholarly achievement documenting the historical development of Arabic vocabulary over centuries. He said the project stands as evidence of Qatar’s steadfast support for scientific research, knowledge production and the preservation and global presence of the Arabic language.

He noted that Qatar’s participation in the Fair

reaffirms its support for cultural and intellectual initiatives, as well as its contributions to

publishing and translation, based on the belief that the book is not just a carrier of knowledge but a universal human message that promotes openness and dialogue beyond borders.

Expressing hope that this year’s New Delhi World Book Fair will provide a vibrant forum for idea exchange, expertise sharing and fostering a love of reading across society, he said Qatar was confident its participation would add meaningful value to the event. He concluded by thanking the organizers, partners in the Republic of India and the media for their continued support and wished the Fair every success.

World’s Largest Global Book Fair Begins

New Delhi: The world’s largest B2C global book fair returns with its 53rd edition in the national capital from 10 January. Organized by the National Book Trust (NBT) with support from the Ministry of Education, Government of India, the nine-day fair will run until 18 January 2026 at Bharat Mandapam, with the India Trade Promotion Organisation as co-organizer.

More than one thousand publishers from over 35 countries will participate, and over one thousand speakers will take part in more than 600 literary and academic events. Over two million visitors are expected. For the first time, entry to the fair will be completely free, reflecting NBT’s commitment to making books and reading more accessible

to the public.

The fair will be inaugurated by Union Education Minister Dharmendra Pradhan. This year, Qatar will be the Guest of Honour and Spain the Focus Country. The central theme pavilion, “Indian Armed Forces: History, Valour and Vision,” will span 1,000 square meters and pay tribute to the Army, Navy and Air Force, showcasing more than 500 books, exhibitions, documentaries, models and special programs. Over 100 sessions featuring defence experts, noted authors and former military officers will highlight leadership, patriotism and national service among youth. Special exhibitions on Vande Mataram and the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel will also be held.

Qatar to showcase culture as Guest of Honor at New Delhi World Book Fair: Jasim Ahmed Al Bouenin

NEW DELHI: Jasim Ahmed Al Bouenin, Director of the Doha International Book Fair, said he was pleased to take part in the press conference for the New Delhi World Book Fair, describing it as a global platform where cultures meet and ideas are exchanged. He said Qatar was honored to be selected as the Guest of Honor this year, represented by the Ministry of Culture of Qatar.

Al Bouenin noted that cultural relations between Qatar and India are rich, deeply rooted and continue to grow through dynamic development and strategic partnerships. He said a wide range of activities and events will be organized at the Qatar Pavilion, including displays of key publications by the Ministry of Culture,

as well as a selection of books translated from Hindi.

He added that the pavilion will also present authentic Qatari heritage, with speakers highlighting Qatari culture and traditions and the role of the Indian community in Qatar’s cultural life, particularly in strengthening cooperation between the two countries. Visitors will also be able to see Qatari handicrafts and enjoy musical performances by a Qatari folk ensemble.

Expressing gratitude, Al Bouenin extended sincere thanks to the organizers of the New Delhi World Book Fair for their efforts and for selecting the State of Qatar as Guest of Honor, wishing them continued success.

ایس آئی آر کے موضوع پر چکر دھر پور مغربی سنگھ بھوم میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد: مولانا احمد حسین قاسمی

نوجوانوں کے علاوہ 14 بی ایل اور 2 ماسٹر ٹرینرز نے ورکشاپ میں حصہ لیا

کے کامیاب انعقاد پر امارت شرعیہ، منتظمین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت مولانا اور ان کے رفقاء ہی کی محنت، توجہ اور موثر حکمت عملی کے نتیجے میں شرکاء کی قابل ذکر تعداد کی موجودگی نہایت خوش آئند رہی۔ یہ منظر خاص طور پر قابل دید تھا کہ اس میٹنگ میں اس ورکشاپ میں 14 سے زائد بی ایل اور تمام بی ایل اوکڑ بینک دینے کے لیے سرکار کی طرف سے نامزد دو ماسٹر ٹرینرز موجود تھے۔ ورکشاپ میں شہر کے عمائدین، سماجی کارکنان، دانشوران اور مختلف ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان بھی شریک رہے۔ ٹریننگ میں امارت شرعیہ بہار اڈیشہ و جھارکھنڈ کے ارباب حل و عقد کے رکن مولانا رکن الدین صاحب مہتمم مدرسہ فیض الحق، جامع مسجد کے امام قاری الطاف صاحب، انجمن اسلامیہ چکر دھر پور کے صدر فیضان منظر، نائب صدر حاجی اکرام، چنل سکریری بیروم خان اور نائب سکرٹری صدام حسین، ماسٹر ٹرینر شاہد اختر اور سہیل صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار ہوئے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ مرکزی دفتر سے ذمہ داران مسلسل وفد کے رابطہ میں رہے۔ اس مہم کا اگلا پڑاؤ 7 تاریخ کو مدھو پور جامع مسجد سلگو یا، دھنی میں منعقد ہوگا اور مدھو پور دفتر دارالقضاء، امارت شرعیہ میں مغرب کے بعد منعقد ہوگا۔



کہ مسلم نوجوان ملک کے شہریوں کے مسائل کے حل میں مثبت اور فعال کردار ادا کریں۔ ریاست جھارکھنڈ میں ہونے والے ایس آئی آر سے متعلق حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی اور ناظم امارت شرعیہ حضرت مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی نہایت فکرمند ہیں کہ کوئی شہری کسی بھی طرح ایس آئی آر کے اس زمرے سے باہر نہ رہ جائے اس موقع پر ریٹائرڈ ماسٹر حاجی محفوظ الرحمن صاحب نے حضرت امیر شریعت مقرر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مظلوم کے اس بروقت اور عوامی مفاد پر مبنی اقدام کو سراہتے ہوئے اسے جھارکھنڈ کے تمام شہریوں کی ایک اہم ضرورت قرار دیا اور پروگرام

امر ہے۔ اپنے صدارتی خطاب میں قائد وفد جناب مولانا احمد حسین قاسمی نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا آدی واسی سانج سے تعلق رکھتے ہوں، بڑی تعداد ایسے غریب اور ناخواندہ افراد کی ہے جن کے لیے پیرنٹل میپنگ اور ایس آئی آر ایک دشوار مرحلہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر بلا تفریق مذہب و ملت ہر شہری، مرد و خواتین، کی مدد کریں۔ آپ نے حدیث نبوی ﷺ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔“ انہوں نے واضح کیا کہ امارت شرعیہ چاہتی ہے

متعلق اہم نکات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جن مقامات پر رجسٹرڈ وقف جائیدادیں ابھی تک امید پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہو سکیں، وہاں ٹریننگ میں درخواست دے کر اپلوڈ کا موقع حاصل کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی قسم کی قانونی دشواری پیش نہ آئے۔ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے شرکاء کے سوالات کے کثیفی بخش جوابات دیے اور عملی رہنمائی بھی فراہم کی اور ان کی ایما پر نوجوانوں اور بی ایل او کی ایک بڑی تعداد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایس آئی آر مکمل ہونے تک ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اس ٹریننگ کے ذریعے عام لوگوں کی مدد کو یقینی بنائیں گے جو امارت شرعیہ کے لیے ایک خوش آئند

چکر دھر پور مغربی سنگھ بھوم: امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ کی جانب سے ایس آئی آر اور پیرنٹل میپنگ سے متعلق جاری ہمہ گیر تربیتی مہم کے تحت ایک اہم اور مفید ورکشاپ ورکشاپ مدرسہ فیض عام، جگن ناتھ پور میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس تربیتی پروگرام کی صدارت معاون ناظم امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ جناب مولانا احمد حسین قاسمی نے فرمائی۔ ورکشاپ کا آغاز مغرب کے بعد حافظ پرویز صاحب کی تلاوت سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض جمشید پور کے نائب قاضی شریعت مولانا افراسیہی القاسمی نے خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ ابتدائی خطاب میں قاضی شریعت جمشید پور حضرت مولانا سعود عالم قاسمی نے ایس آئی آر کی اہمیت، اس کے سماجی اثرات اور عوامی شمولیت کی ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بعد ازاں امارت شرعیہ ریسرچ ٹیم کے رکن مفتی قیام الدین قاسمی نے پروجیکٹر پر پریزنٹیشن کے ذریعے شرکاء کو عملی تربیت دی۔ انہوں نے پیرنٹل میپنگ، فارم 6، فارم 8 اور ایس آئی آر سے متعلق پیچیدہ امور کو نہایت سادہ، عام فہم اور عملی انداز میں سمجھایا، جس سے شرکاء کو براہ راست فائدہ حاصل ہوا۔ شرکاء نے مجلس میں ان کاموں کو پریکٹیکل بھی انجام دیا۔ اس موقع پر امارت شرعیہ کے وفد ریسرچ ٹیم کے رکن ڈاکٹر حفظ الرحمن حفظ نے وقت سے

28 جنوری کو کمبا کونم میں آئی یو ایم ایل کی جانب سے محلہ جماعت ریاستی کانفرنس کا انعقاد



ترویجی (پریس ریلیز) انڈین یونین مسلم لیگ (آئی یو ایم ایل) کی جانب سے 28 جنوری 2026 کو کمبا کونم میں محلہ جماعت ریاستی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی صدر پروفیسر کے ایم قادری الدین نے 2 جنوری کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے پارٹی کے صدر عزت تائب تھلاپتی ایم کے اسٹالن سے ترویجی میں ملاقات کی اور کمبا کونم میں منعقد محلہ جماعت ریاستی کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا۔

گاؤں جوار میں تاش کھیلنے کے تنازع پر پتھر اور متعدد افراد زخمی

علی گڑھ، علی گڑھ کے اگلا س کوتوالی حلقہ کے گاؤں جوار میں تاش کھیلنے کے تنازع نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ دو فریقوں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کے بعد دونوں جانب سے شدید پتھر اڑا ہوا، جس کے نتیجے میں نصف درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے ہی اگلا س تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حالات پر قابو پایا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 10 سے 12 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعہ کی ویڈیو شل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس سے گاؤں میں چہلموئیاں جاری ہیں۔ زخمی خوشحالی سنگھ نے بتایا کہ وہ کھیت سے واپس آ رہے تھے کہ گاؤں پہنچتے ہی دونوں جوانوں نے انہیں روک لیا اور دیگر افراد کو بلا کر حملہ کر دیا۔ ان کے مطابق لاشی، ڈنڈے، اینٹ اور چاقو جیسے تھپیروں کا استعمال کیا گیا، جس میں تقریباً دس افراد زخمی ہوئے، جبکہ چار افراد بے شکل موٹر سائیکل کے ذریعے فرار ہو سکے۔ اس سلسلے میں سی او اگلا س پمیش مار نے بتایا کہ تاش کھیلنے کے تنازع پر دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جو بعد میں پتھر اڑاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ چند افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے تحت گاؤں جوار میں پولیس پکٹ تعینات کر دی ہے۔ تحریری شکایت موصول ہونے پر ضروری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام کے مطابق فی الحال گاؤں میں امن و امان کی صورتحال قابو میں اور معمول پر ہے۔

ہیرا گروپ آف کمپنیز اور ڈاکٹر نوہیرا شیخ کی حقیقت اور سچائی

سازشوں، قانونی لڑائیوں اور سرمایہ کاروں کی ادائیگیوں کا جائزہ



نئی دہلی: ہیرا گروپ آف کمپنیز اور ڈاکٹر نوہیرا شیخ کا معاملہ آج ہندوستان بھر کا بحث میں معمہ بنا ہوا ہے، لیکن جتنی آسانی سے لوگ کسی شخص کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کیلئے اپنے ذہن و دل اور یادداشت پر زور نہیں ڈالتے، کیونکہ سوچنے اور شفاف فیصلے پر پہنچنے کیلئے ماضی کی یادوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، انسان منفی سوچ کا معمہ ہوتا ہے اور منفی خبر کو اچھالنے اور اس کو بحث کا ذریعہ بنانے میں اسے مزہ بھی آتا ہے، چند ایک بار اپنی بغض و عناد کا بھی شمولیت کر لیتا ہے تو دوسروں کیلئے انصاف سے بہت دور ہو کر فیصلے لیتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے، اس پر مزید سونے پر سہا گاہ کہ یہ بکائے گئے بلیس کے چیلوں اور شیطانیوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا بھی کردار شامل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے سرکش و فریبی شخص جب حریف کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پہلے اسے عوامی سطح پر بدنام اور کمتر درجے میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دیگر حربے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اسی لئے کتاب مقدس میں فرمایا گیا کہ جب کوئی فاسق فاجر خبر پھیلائے تو جانچ پڑتال کر لیا کرو، ہمیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی اور ناگہمی میں کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہارے پاس پھینچتے ہوئے کے سوا کوئی چارانا ہو۔ ٹھیک اسی طرح ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ہمارا ہا ہے، خاص تو خاص عام لوگ جن کو حقیقت حال سے کوئی واقفیت نہیں ہے وہ ہیرا گروپ اور اس کی کسی ای او عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے، جب کہ لوگوں کو ہیرا گروپ کی سچائی اور اس کی حقیقت اور اس پر کئے

گئے سازش حیلے کی حقیقت کو لوگ نہیں جانتے اور سمجھتے۔ ماضی قریب کی بات کریں تو ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے عروج کے ایام طے کرتے ہوئے فلاح و بہبود کی نئی نوبلی شروعات پر قدم رکھتی جا رہی تھی، دشمن عناصر جو ابھی تک خدشات کے پیچھے ہیرا گروپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب حتیٰ فیصلے کیلئے سید سپر ہو گئے اور کمر بستہ ہوتے ہوئے ہیرا گروپ سی ای او کو گرفتار کر دیا گیا، لیکن با بنیاد سی ای او نے ہار نہیں مانی، عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ نے اپنی سچائی اور حقیقت کی بنیاد پر ہر محاذ کی ذمہ داری سنبھالی اور ملک کے قانون پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہر سازش کا جواب دیا، ایک جانب ہیرا گروپ کے دفاتر پر تالے لگا دئے گئے تو دوسرے طرف کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہراساں کیا گیا۔ جانچ کے نام پر تمام ریکارڈ کسٹریکشن کرنے کی کوشش کی گئی، ان سب کے درمیان ہیرا گروپ سی ای او نے جو بھی گراں قدر شہور میں سونے کے زیورات کمپنی کے ہاتھ میں تھے انہیں سرمایہ کاروں میں تقسیم کر دیا گیا، ڈھائی

سال جیل میں رکھنے کے بعد جب ڈاکٹر نوہیرا شیخ کی رہائی ہوئی تو اپنی وساطت اور وسعت کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں افراد کو ایسے وقت میں ادائیگیاں کی گئیں جب ان کے بینک اکاؤنٹ ختم تھے اور جائیدادیں ضبط تھیں، یعنی کہ تمام وسائل پر تالے لگے ہوئے تھے، عوام کو سمجھنا چاہئے کہ ایک با بنیاد تجارت اور اس کی مالک کس طرح لوگوں کیلئے فکر مند ہے اور آج بھی اسی مستعدی سے قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اگر ایک لاکھ روپے بھی ڈاکٹر نوہیرا شیخ کے ہاتھوں میں میسر ہوئے تو مستحقین تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ان سب سازشوں کی بنیاد 2008 سی رچی گئی اور پہلا قدم 2012 میں اٹھایا گیا، جب حیدر آباد کے ممبر پارلیمنٹ نے حکومت سے ہیرا گروپ کمپنی کی جانچ کا مطالبہ کیا اور ایف آئی آر کیا، تا نصرف جانچ کا مطالبہ کیا بلکہ اس کی پیروی خود کرنے کی ٹھانی۔ با بنیاد اور ٹھوس ثبوتوں کے ادھار پر ہیرا گروپ آف کمپنی اور سی ای او عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ نے مقدمہ جیت لیا اور بیرسٹر مانے جانے کا سبب بھی بنائیں۔

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, लक्ष्मी नगर यूनिट के तहत ललिता पार्क में कार्यालय का उद्घाटन

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, लक्ष्मी नगर यूनिट के अंतर्गत आज ललिता पार्क में संगठन के कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन ज़िला नाज़िम, इंजीनियर अब्दुल मन्नान ने किया।

इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में साप्ताहिक सदाए अंसारी के संपादक अतहर हुसैन अंसारी, एक मीनार मस्जिद के मुतवल्ली एवं दौर-ए-जदीद उर्दू अखबार के संपादक शहरोज़ रज़ा, ताज एन्क्लेव से जमाअत के सदस्य वासिक इमाम, जगतपुरी से सदस्य असलम तथा लक्ष्मी नगर के स्थानीय अमीर फ़लाहुद्दीन फ़लाही विशेष रूप से शामिल हुए।

कार्यालय के उद्घाटन के बाद औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फ़लाहुद्दीन फ़लाही ने दर्स-ए-कुरआन प्रस्तुत किया। उन्होंने पवित्र कुरआन की सूरह अस-सफ़ की तिलावत के बाद उसका अनुवाद और विस्तृत व्याख्या की। दर्स के दौरान सूरह



की उपयोगिता, उसका आशय, पृष्ठभूमि और व्यावहारिक संदेश पर प्रकाश डाला गया तथा अंत में सूरह अस-सफ़ का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के समापन पर पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यालय और दर्स-

ए-कुरआन के माध्यम से क्षेत्र में धार्मिक जागरूकता, वैचारिक प्रशिक्षण और जमाअती गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, लक्ष्मी नगर यूनिट के अंतर्गत आराम पार्क, गली नंबर चार में पिछले एक वर्ष



से नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो नमाज़-ए-इशा के बाद होते रहे हैं। अब ललिता पार्क में भी औपचारिक रूप से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, ताकि दोनों स्थानों पर धार्मिक और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियाँ निरंतर जारी रह सकें।

हिमाचल प्रदेश ने भूतान को भेंट किए चिलगोज़ा के पौधे

मुख्यमंत्री ने वाहन को हरी झंडी दिखा दिया खाना



मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुखबू ने आज प्रदेश सचिवालय शिमला से भारत और भूतान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए भूतान को चिलगोज़ा के पौधों का उपहार प्रेषित किया।

वाहन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत और भूतान के मैत्रीपूर्ण, सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा भूतान को पांच लाख रूपये मूल्य के चिलगोज़ा के और बीज भी प्रदान किये जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भूतान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोज़ा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया

जाएगा। इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी। प्रदेश सरकार चिलगोज़ा गतिविधियों में स्थानीय महिला मंडलों को भी शामिल करेगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी भूतान को चिलगोज़ा के 50 किलोग्राम बीज प्रदान किए जा चुके हैं।

चिलगोज़ा पश्चिमी हिमालय की बहुमूल्य प्रजाति है, जो पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता और स्थानीय आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई है।

ठाकुर सुखविन्द सिंह सुखबू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार वन संवर्धन के लिए अनेक पहल कर रही है और राज्य में वन

आवरण के विस्तार को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार के प्रयासों से वन क्षेत्र लगभग 55 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इस वर्ष लगभग 9000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधरोपण किया जा रहा है, इसमें 60 प्रतिशत फलदार पौधे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधरोपण किया गया है।

वनों की रक्षा एवं प्रबन्धन के लिए 2019 वन मित्र की नियुक्ति की गई है, जिन्हें वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा, राल दोहन सहित विभिन्न वानिकी कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार जन सहयोग से हरित आवरण में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ग्रीन एडॉप्शन योजना सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उप-मुख्य सचिव केवल सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम केहर सिंह खाची, विधायक कैप्टन रणजीत सिंह राणा एवं मलेन्द्र राजन, प्रदेश हज कमिटी के अध्यक्ष दिलदार अली भट्ट, महाधिवक्ता अनूप रतन, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान मुख्य अरण्यपाल संजय सूद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



امارت شرعیہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کی جانب سے منظم طور پر ایس آئی آر بیداری مہم جاری

کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وقف جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے آزاد کرا کے انہیں شرعی اور سماجی مصرف میں لانا وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، انہوں نے وقت کی جائیداد سے متعلق لوگوں کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دیے۔ دوسرے مرحلے میں مفتی قیام الدین قاسمی اور مفتی اکرام الدین قاسمی نے پروجیکٹر اور پریزنٹیشن کے ذریعے ایس آئی آر کی عملی تربیت دی۔ انہوں نے نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں ایس آئی آر کے تمام تکنیکی مراحل، مطلوبہ دستاویزات اور احتیاطی نکات کی وضاحت کی، اور شرکاء کو موقع پر ہی عملی مشق بھی کرائی، جس سے پروگرام کی افادیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ شرکاء کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے اور عملی مسائل کے قابل عمل حل پیش کیے گئے۔ آخر میں شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایس آئی آر کے مرحلے میں عوامی رہنمائی کو اپنا سماجی اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے گھر گھر جا کر یہ خدمت انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ جھارکھنڈ میں جاری یہ بیداری مہم حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی کی نگرانی میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظم امارت شرعیہ حضرت مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی، نائب ناظم جناب مفتی محمد سہراب ندوی قاسمی، قاضی شریعت مرکزی دارالافتاء جناب مفتی محمد انظار عالم قاسمی اور دیگر ذمہ داران کی یہ کوشش ہے کہ جھارکھنڈ کی عوام اقلیت ہوں یا اکثریت کسی بھی مرحلے میں دشواری کا شکار نہ ہوں۔ گڈا کے تمام پروگراموں کی ترتیب و انعقاد میں جناب مولانا شمس پرویز مظاہری صدر تنظیم امارت شرعیہ ضلع گڈا اور رابطے مدارس اسلامیہ کے دیگر ذمہ داران نے نمایاں کردار ادا کیا۔



موضوع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نسل نو کی دینی تربیت محض ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ملت کی بقا کی شرط ہے، اور آج کے دور میں دینی شعور کے ساتھ آئینی و قانونی آگہی بھی ناگزیر ہو چکی ہے۔ امارت شرعیہ کا تقاضہ ہے کہ ملت کا ہر فرد ہر وقت باشعور رہے، اور خوب اچھی طرح سمجھے کہ ایس آئی آر آسامی شعوری جدوجہد کا ایک عملی مرحلہ ہے، جس کا مقصد ہر بستی میں ایسے باشعور نوجوان تیار کرنا ہے جو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ عوام کی رہنمائی کر سکیں، اور اس نتیجے میں ملت اسلامیہ ہر وقت تمام احوال سے باخبر رہے۔ وہیں اس موقع پر مولانا ڈاکٹر حفیظ الرحمن حفیظ نے وقف کے تحفظ کے نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ نئے وقف ایکٹ کے تحت وقف جائیدادوں پر لاء آف مینیشن کا اطلاق ہوگا، جس کے نتیجے میں غفلت کی صورت میں ناقابل تلافی نقصانات سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک محض زمین یا عمارت نہیں بلکہ ملت کی امانت اور آنے والی نسلوں کا سرمایہ ہیں، اور ان کا تحفظ محض تقریروں سے نہیں بلکہ تدبیر اور عملی اقدام سے ممکن ہے۔ انہوں نے تحفظ اوقاف

مدرسہ اسلامیہ عربیہ خرد سائھی میں بھی ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں نوجوانوں اور علاقے کے دانشوروں نے شرکت کی۔ ان تمام پروگراموں کی صدارت امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ کے معاون ناظم مولانا احمد قاسمی نے فرمائی، اور انہی کی قیادت میں یہ وفد ریاست کے مختلف علاقوں میں عوامی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اپنے صدارتی اور کلیدی خطاب میں مولانا احمد حسین قاسمی نے امارت شرعیہ کی گراں قدر خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امارت نے ہمیشہ دین و شریعت کی حفاظت کا کام انجام دیا ہے اور تاریک حالات میں شمع بصیرت جلانے کا کام کیا ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ جب بھی ملت کو دینی، تعلیمی، سماجی یا آئینی سطح پر چیلنج درپیش ہوا، امارت شرعیہ نے احتجاج کے شور کے بجائے تعمیری خاموش مگر موثر زبان اختیار کی اور عملی میدان میں اتر کر کام کیا۔ انہوں نے ضلع گڈا کے موجود علماء اور ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی حضرات امارت شرعیہ کے دست و بازو ہیں، آپ کو خامہ وقت عمارت شرعیہ کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، انہوں نے تعلیم کے

گڈا: قوموں کی زندگی محض جذباتی نعروں سے نہیں، بلکہ شعور، نظم اور منسلح محنت سے عبارت ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے حالات کو سمجھنے، اپنے حقوق کو پہچاننے اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے، وہی تاریخ کے دھارے میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ نے ریاست جھارکھنڈ میں ایس آئی آر کے سلسلے میں جو بیداری مہم اور عملی تربیتی پروگرام شروع کیا ہے، وہ وقتی اقدام نہیں بلکہ ملت کے فکری، سماجی اور دستوری مستقبل کی ایک سنجیدہ اور دور رس جدوجہد ہے جس کے اثرات پوری ریاست میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج جامعہ محمودیہ عربیہ مال پرتاپور اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ خرد سائھی میں ایس آئی آر کی تربیتی نشستیں منعقد ہوئیں، جن کا مقصد عوام کو محض معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ انہیں ایسا باخبر شہری بنانا ہے جو اپنے آئینی حقوق و فرائض سے واقف ہو اور دوسروں کی رہنمائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ پوری تحریک اس فکری رہنمائی کا مظہر ہے جو حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی مدظلہم کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہے؛ ایک ایسی قیادت جو حالات پر شکوہ کرنے کے بجائے حالات کو سنوارنے پر یقین رکھتی ہے، اور جو وقتی اشتعال کے بجائے دور اندیش حکمت عملی کو ترجیح دیتی ہے اور ایک منظم سماج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آج مورخہ 12 جنوری کو ضلع گڈا کے مہرماں بلاک کینال پرتاپور میں وسیع پیمانے پر بیداری پروگرام اور عملی تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی، جہاں سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا جبکہ بعد ازاں ظہر ضلع گڈا کے بسنترائے بلاک میں واقع

کرائم کی خبریں

تلنگانہ: خفیہ خزانہ کی تلاش۔ گروہ گرفتار

حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع یادادری جھوگیر کے گاؤں ماداپور میں خفیہ خزانہ کی تلاش کرنے والے گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کرتے ہوئے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے ایک شخص نے مادھاپور میں زرعی اراضی خریدی تھی اور اس کی نگرانی کے لئے ای سی آئی ایل کے ساکن کی کارسوامی کو سو پروائز مقرر کیا تھا۔ اس اراضی میں ایک چھوٹی پہاڑی پر مورتی ہے۔ کارسوامی نے اپنی محدود آمدنی میں اضافہ اور راتوں رات امیر بننے کے لالچ میں ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت اس نے یہ گمان کیا کہ مجسمہ کے نیچے زمین میں قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اپنے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کارسوامی نے وجئے واڑہ، کھیم اور بولارام سے تعلق رکھنے والے پانچ دیگر افراد کے ساتھ مل کر ایک گروہ بنایا۔ مقامی دیہاتیوں کو شک سے بچانے کے لئے اس گروہ نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ وہ زرعی کنوئیں کی کھدائی کر رہے ہیں۔ ملزمین نے مخصوص پوجا کی اور ہنچاچی مٹین کے ذریعہ مجسمہ کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ گاؤں والوں کو ان کی پراسرار سرگرمیوں پر شبہ ہوا جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر تمام 6 ملزمین کو روکنے لگا۔ انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تلاشی کے دوران پولیس نے ایک ہنچاچی مٹین، ایک کار اور پوجا کا سامان قبضہ میں لے لیا۔ پولیس حکام نے واضح کیا کہ گروہ پرستی کی بنیاد پر خفیہ خزانوں کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کارروائی جرم ہے اور عوام کو چاہیے کہ ایسی کسی بھی سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔

تلنگانہ: پولیس اسٹیشن سے چار قیمتی مرغ غائب

حیدرآباد: تلنگانہ کے ضلع ملکنڈہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جہاں پولیس اسٹیشن سے وہ چار قیمتی مرغ غائب ہو گئے جنہیں پولیس نے مرغوں کی لڑائی کے خلاف کارروائی کے دوران ضبط کیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق سنکرائی تہوار کے پیش نظر تلگور یا ستوں تلنگانہ اور اے بی میں مرغوں کی لڑائی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ غیر قانونی ہے لیکن اسے روایت کے نام پر کھلایا جاتا ہے۔ ملکنڈہ شہر کے مضافات میں مرغوں کی لڑائی کی اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس پولیس نے چھاپہ مارا اور چار مرغوں کو پکڑ کر نوٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ یہ مرغ عام نہیں تھے بلکہ انہیں ایک سال تک بادم، کاچا اور پیسے جیسی قیمتی غذائے غذا دے کر خاص طور پر لڑائی کے لیے تیار کیا گیا تھا اور مارکت میں ان کی قیمت تقریباً 60 ہزار روپے بتائی جا رہی ہے تاہم جب ان مرغوں کو پولیس اسٹیشن لایا گیا تو وہ وہاں سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ اس واقعہ نے جہاں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، وہی یہ معاملہ پورے ضلع میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

چینی مانجہ کے خطرناک اثرات

حیدرآباد: پتنگ بازی کیلئے چینی مانجہ کے خطرناک اثرات سے متعلق عوامی شعور بیدار کرنے کی ایک ٹریفک پولیس ملازم کی انوکھی کوشش سوشل میڈیا پروائرل ہو رہی ہے۔ پولیس ملازم نے ایک کھیرے کا استعمال کرتے ہوئے یہ دکھایا کہ چینی مانجہ کتنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح گہرے زخم لگا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پولیس ملازم ایک لڑکے کی کونسلنگ کر رہا ہے جو چینی مانجہ استعمال کر رہا تھا۔ اس ملازم پولیس نے سوال کیا کہ کیا تم پتنگ اڑانے کے لئے عام دھاگہ استعمال نہیں کر سکتے؟ چینی مانجہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عملی مظاہرے کے ذریعہ دکھایا کہ جس طرح مانجہ نے کھیرے کو آسانی سے کاٹ دیا، اسی طرح یہ انسانی جلد اور روگوں کے لئے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ پولیس ملازم نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ چینی مانجہ کے بجائے سوتی دھاگے کا استعمال کریں کیونکہ چینی مانجہ عوامی تحفظ کے لئے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مانجہ سڑک پر چلنے والے ٹوہیلر سواروں کے گلے پر لگ کر مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جہاں بایک سوار اس خطرناک چینی مانجہ کی زد میں آ کر اپنی جان گنوا بیٹھے جس کے پیش نظر حکام بار بار اس کے استعمال کے خلاف وارننگ جاری کر رہے ہیں۔

اے پی کے ضلع کڑپہ میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی

حیدرآباد: آندھرا پردیش کے ضلع کڑپہ کے سدھاوٹم منڈل میں تیندوے کی نقل و حرکت نے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ جنگلی جانوروں کے انسانی بستیاں کا رخ کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات نے دیہی علاقوں کے عوام کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں مولاپلی میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب مقامی افراد نے ایس سی کالونی کے قریب ایک تیندوے کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کے شور مچانے پر تیندوہ اتر رہی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اطلاع ملنے ہی محکمہ جنگلات کے حکام موقع پر پہنچ گئے اور چیتے کے قدموں کے نشانات کی مدد سے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ جنگلات سے متصل ہے جو کہ ٹائیگر زون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھنے جنگلات کے قریب ہونے کی وجہ سے اکثر جنگلی جانور خوراک یا پانی کی تلاش میں رہائشی علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ حکام نے گاؤں والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خاص طور پر رات کے وقت اور صبح سویرے انتہائی محتاط رہیں اور اکیلے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ دوسری جانب، مولاپلی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں تیندوے کی آمد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی فکر مند ہیں۔ انہوں نے حکومت اور محکمہ جنگلات سے مطالبہ کیا ہے کہ تیندوے کو فوری طور پر پکڑ کر گھنے جنگل میں منتقل کیا جائے تاکہ انہیں تحفظ مل سکے۔

تعلیم کے ساتھ صحت پر توجہ وقت کی اہم ضرورت ہے: وائس چانسلر پروفیسر اے تیجا



پروان چڑھے گی، جسمانی فٹنس کے ساتھ نظم و ضبط اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور یونیورسٹی کا تعلیمی و سماجی ماحول مزید صحت مند اور متحرک بنے گا۔ اس افتتاحی تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر اڈھم سنگھ، وارڈن ڈاکٹر منیش کمار، وارڈن ڈاکٹر کوشلش کمار شاہ، ڈاکٹر نلنی مشرا ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر ترپاٹھی، پرائکٹر ڈاکٹر نیرج شکلا، ڈاکٹر لکشمی سنگھ کے علاوہ دیگر اساتذہ، انتظامی عملہ اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور اس نئی سہولت کو یونیورسٹی کے لیے ایک خوش آئند اضافہ قرار دیا۔

مشینیں، مختلف اقسام کے کارڈیو آلات کے ساتھ ساتھ یوگا اور اسٹریٹجک کے لیے الگ اور پرسکون جگہ بھی مختص کی گئی ہے تاکہ طلبہ اپنی جسمانی قوت کے ساتھ ذہنی سکون اور توازن بھی حاصل کر سکیں۔ وائس چانسلر نے مزید کہا کہ یہ سہولت نہ صرف بوائز ہاسٹل کے طلبہ بلکہ یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملازمین کے لیے بھی مکمل طور پر مفت فراہم کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یونیورسٹی کے تمام افراد میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس جدید جمنازیم کے قیام سے طلبہ میں ورزش کی عادت

لکھنؤ: واجہ معین الدین چشتی لینگوتج کے سہاش چندر بوس بوائز ہاسٹل میں سوامی وویکا نند کے یوم پیدائش کے موقع پر بوائز ہاسٹل میں طلبہ کو جسمانی و ذہنی صحت کے تئیں بیداری اور فعال اور صحت مند زندگی گزارنے کے لئے ایک جمنازیم کا افتتاح کیا۔ یہ افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اے تیجا کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر اے تیجا نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کی جسمانی و ذہنی صحت پر ہی ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ سوامی وویکا نند کے افکار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مضبوط جسم کے بغیر مضبوط ذہن اور بلند حوصلہ ممکن نہیں۔ آج کے مسابقتی اور چیلنجوں سے بھرپور دور میں ضروری ہے کہ طلبہ نہ صرف تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں بلکہ اپنی صحت و تندرستی پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ پروفیسر اے تیجا نے کہا کہ بوائز ہاسٹل میں جمنازیم کا قیام اسی سوچ کا عملی اظہار ہے تاکہ طلبہ ایک متوازن، فعال اور صحت مندر طرز زندگی اختیار کر سکیں۔ انھوں نے طلبہ کو تلقین کی کہ وہ اس سہولت سے بھرپور استفادہ کریں، باقاعدگی سے ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور خود کو جسمانی و ذہنی طور پر مضبوط بنائیں تاکہ نہ صرف اپنی شخصیت کو نکھاریں بلکہ قوم و ملک کی تعمیر میں بھی موثر کردار ادا کریں۔ انس موقع پر انھوں نے کہا کہ سہاش چندر بوس بوائز ہاسٹل میں قائم کیا گیا یہ جدید جمنازیم تمام عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور جدید و معیاری آلات سے پوری طرح آراستہ ہے۔ جمنازیم میں ٹریڈ مل، جدید ویٹ ٹریننگ